SHRI VASANT SATHE (Akola):
I have not got it.

PROF. MADHU DANDAVATE:
Sir, you are keeping quiet with a
vengeance.

15.07 hrs.

RESERVE BANK OF INDIA (AM-
ENDMENT) BILL—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri
Madhu Limaye.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, यह रिजर्व बैंक कानून में संशोधन करने वाला जो विधेयक हमारे सामने रखा गया है उसके बारे में मैं सब से पहले यह अर्थ करना चाहता हूँ कि इस तरह पीसमीलिंग से इस कानून का प्राथमिकीकरण अच्छा नहीं है। बुनियादी तौर पर रिजर्व बैंक एक्ट के बारे में सरकार को सांचना चाहिए और एक नया कानून सदन के सामने पेश करना चाहिए। हर एक दो साल के बाद इस तरह के विधेयकों को पास करने का कोई मतलब नहीं होगा।

दूसरी बात यह है और यह बहुत चिन्ता की बात है कि रिजर्व बैंक को जो स्वायत्तता है उस स्वायत्तता को इस सरकार ने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। फाइनेंशियल इस्टीमेट्स लाज की ज्याइंट पालयामेंट्री कमेटी में एक बहुत ही अनोखी घटना हुई जिस की तरफ मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री जगन्नाथ साहब जो आई सी एस है, कमेटी के समक्ष गवाही देने के लिए आए थे। उन से मैं ने एक सीधा प्रश्न पूछा कि इस कानून के बारे में सरकार के पास आप ने अपनी राय भेजी थी और अगर भेजी थी तो क्या हम कानून के बुनियादी सिद्धांतों से आप का विरोध है? तो गवाही देने वाले रिजर्व बैंक के गवर्नर क्या जवाब देते हैं कि सरकार से सलाह मांगविरा कर के और सरकार की इजाजत लेकर मैं आप के

के प्रश्न का उत्तर दूंगा। ज्याइंट पालियामेंट्री कमेटी का उन्होंने अपमान तो किया ही लेकिन इस से रिजर्व बैंक के गवर्नर की मनोदशा के ऊपर प्रकाश पड़ता है। इस सरकार ने सारे अफसरों को इस तरह गुलाम बना दिया है कि स्वायत्तता की बात तो आप करेंगे लेकिन ज्याइंट पालियामेंट्री कमेटी के सामने एविडेंस देने के लिए बह तैयार नहीं है इस डर से कि मन्त्री महोदय क्या कहेंगे? क्या यह घटना हुई है या नहीं, इस की सफाई सुशीला जी को देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप को सही सलाह मिले, उस को आपमानेन माने, लेकिन अफसरों के मन में इस तरह का डर उत्पन्न होगा तो कोई सरकार चल नहीं पायेगी फिर यह चमचा लोगों की हो सरकार होगी। तो रिजर्व बैंक की स्वायत्तता के बारे में वह सफाई दें।

अब मैं इस के प्रमुख क्लोज़ की तरफ आ रहा हूँ। . . . (व्यवधान) . . . आप अगर शशिभूषण जी, उस दिन आते तो आप को मुझसे ज्यादा गुस्सा आता। मैं तो सिर्फ वाक आउट कर के ही चला आया, लेकिन शायद आप तमाचा ही मार देते। इसलिए आप बहुत ज्यादा नाराज मत होइए।

उपाध्यक्ष महोदय, चतुर्थ क्लोज़ में इन्होंने यह कहा है कि रिजर्व बैंक के डायरेक्टर्स 4 साल में नियुक्त किये जायेंगे। लेकिन बाद में यह कहा है कि जब तक उन के सक्सेसर्स नियुक्त नहीं किये जायेंगे तब तक पुराने डायरेक्टर्स ही चलते रहेंगे। इस तरह के सुझाव का क्या मतलब है—मेरी समझ में नहीं आता है। अब आप को मालूम है कि फलां डायरेक्टर चार साल के लिये नियुक्त किया गया है उस की मीयाद फलां तारीख को खत्म हो जायगी तो क्या 4 साल में भी आप सक्सेसर के बारे में निर्णय नहीं कर पायेंगे। जिस तरह से गवर्नरों को टर्म खत्म होने के बाद चालू रखते हैं उसी तरह से डायरेक्टरों के बारे में भी करना चाहते हैं—इस का मैं सख्त विरोध करता हूँ।

[श्री मधु सिमरै]

जब मोगरजी देसाई वित्त मंत्री थे, मैंने कई बार सुझाव दिया था कि लगातार आई० सी० एस० भ्रफपरों को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाते चले जा रहे हैं—यह गलत बात है। ऐंसे विशेषज्ञों को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाइये जो फिसकल और मोनिटरी पालिसी के बारे में जानकारी रखते हों। लेकिन अभी तक इस के बारे में सरकार ने कोई पालिसी डिस्क्रिबन नहीं लिया। इस लिये सुशीला जी से प्रार्थना करूंगा—जब आप हमारे मुद्दों का जवाब दे तो इस के बारे में भी खुलासा कीजिये कि भविष्य में इस तरह के आई० सी० एस० या आई० ए० एस० लोगों को नियुक्त नहीं किया जायगा और रिजर्व बैंक के गवर्नर विशेषज्ञों को ही बनायेंगे।

इन्होंने अपने इस विधेयक में बैंको का जो टाइम डिपॉजिट या कुल मिला कर जो डिपॉजिट होते हैं उस का 1 प्रतिशत री-फाइनेंस फैसिलिटा का रूप में देने का सुझाव दिया है। यदि बैंकिंग डिपॉजिट 12 हजार करोड़ मान लिया जाय तो यह रकम 120 करोड़ रुपये हो जायगी। 120 करोड़ रुपये की रकम कोई मामूली रकम नहीं है। क्या मंत्री महोदय कोई इस प्रकार का आश्वासन देंगे कि यह 120 करोड़ रुपये का क्रेडिट ऋषि या उद्योगों के सैक्टर में केवल उन्हीं को मिलेगा जिन को आप ने बरीयत दी है। सरकार के द्वारा जो प्रायोरिटीज निश्चित की गई है उन्हीं के द्वारा रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया जायगा—इस का मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ।

मन्त्री जी को पता होगा कि हमारे यहाँ नम्बर्ड या अन्य चार-पाच बड़े शहरों में हुण्डी बिजनेस चलता है, इस में वे बैंको के द्वारा कर्ज लेते हैं। माल लीजिये 16 परसेन्ट या 18 परसेन्ट से लिया, लेकिन कानून तोड़ कर 25-30 परसेन्ट पर हुण्डीवाले लोग धन्धा करते हैं। क्या बैंको के द्वारा क्रेडिट इस लिये दिया

जाता है कि ये हुण्डीवाले गैर-फानूनी ढंग से रुपया कमाने का काम करें। हुण्डी बिजनेस पर सरकार को टुरन्ट निर्णय लेना चाहिये, इस को समाप्त कर देना चाहिये।

अब डिपॉजिट्स के मतले को लेता हूँ। नान-बैंकिंग कम्पनीज के द्वारा ग्राम लोगों से डिपॉजिट्स लिये जाते हैं। इस के बारे में आज तक बहुत ही थोड़ा बरती गई है। देवकरण नानजी कम्पनी के बारे में मन्त्री जी को पता होगा—उस कम्पनी का जो चलाने वाले थे वे पब्लिक का एक करोड़ रुपया खा गये, अब यह कम्पनी कापड़िया ने ले ली है जिन पर यह सरकार बहुत मेहरबान है। एक चोर दूसरे चोर के हाथ में यह कम्पनी चली जा रही है—मैं जानना चाहता हूँ रिजर्व बैंक क्या कर रहा है नैशनलाइज्ड बैंक क्या कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रिजर्व बैंक के डिपॉजिट्स के बारे में जो नियम है, उन की कापी नहीं है। मैं दो दिन से माग रहा हूँ। चूँकि इस समय आप सभापतित्व कर रहे हैं, इस लिये मैं जानना चाहता हूँ—क्या पार्लियामेंट की लाइब्रेरी इसी तरह से चलेगी, हम को जो जानकारी चाहिये क्या वह हम को नहीं मिलेगी ? दो दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि रूल्ज मिल जाय लेकिन नहीं मिले। यह कोशिश इस लिये कर रहा था कि वर्तमान रूल्ज के अनुसार कम्पनियों का जो शेयर कैपिटल होता है उस का 25 प्रतिशत वे ग्राम जनता से डिपॉजिट के रूप में ले सकती हैं और डायरेक्ट्स की व्यक्तिगत गारण्टी पर वे 25 प्रतिशत और ले सकती हैं, जब कि डायरेक्ट्स के कोई व्यक्तिगत एसेट्स नहीं होते। चूँकि डिपॉजिट्स के बारे में आपने इस में कुछ सुझाव रखे हैं इस लिये मैं जानना चाहता हूँ कि इस से जो धोखिलिया और गड़बड़िया चल रही हैं क्या आप लोग उस पर कोई नियन्त्रण कर पायेंगे।

अब भारत के एक बड़े शेयर होल्डर की बात आप के सामने रखना चाहता हूँ—यह

मधुसूदन लि० है जो भारत के मेजर शेअर होल्डर हैं। इन्होंने डिपॉजिट्स के लिये एडवर्टाइज किया है और 22 परसेंट इन्टरेस्ट देने को तैयार हैं। ये कम्पनियां भारत लि० कम्पनी जैसी कम्पनियों में रुपया लगा रही हैं जो घाटे में चलने वाली है, जिन में दुनिया भर के बदमाश इकट्ठे किये गये हैं। आप के यहां आने से पहले आज सुबह जब मैं अगले सप्ताह के बिजनेस पर बोल रहा था.....

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमति सुशीला चौहान) : जब आप ने कहा था, तब मैं यहाँ मौजूद थी।

श्री मधु लिखये : आप को पता चलेगा कि दो स्मगलरों ने भारत में 30 हजार और 15 हजार शेअर लिये हुए हैं, जिन की कीमत होती है—3 लाख और डेढ़ लाख रुपया। यह भी इसी तरह की कम्पनिया है, जाजोदिया और तुलसियान की। क्या आप इन के बारे में जांच करायेंगी कि पब्लिक के पैसों का किस दुरुपयोग किया जा रहा है।

श्री मधु लिखये : भारत पर आशय—मैंने भारत की बिनेस शीट को बड़ी मेहनत से प्राप्त किया है यह बीनेस शीट बहुत जल्दी नहीं मिलती है? इस से पता चलेगा कि इन का जो पेड-अप कैपिटल है, उस से दुगने से भी अधिक....

MR. DEPUTY-SPEAKER: I want to know where is the connection of Maruti Limited with Reserve Bank of India?

श्री मधु लिखये : डिपॉजिट्स के बारे में कह रहे हैं नान-बैंकिंग कम्पनीज के द्वारा पब्लिक से जो डिपॉजिट्स लिये जाते हैं, उस में जो घोटाला होता है, उस को बैंक बरने के लिये इन्होंने इस बिल में उसकी व्याख्या की है। इसलिये इस महत्वपूर्ण अंग की ओर आप का ध्यान दिला रहा हूँ। मैं कह रहा था कि जो ऐसी कम्पनियां हैं, जिन के ऊपर सरकार का बरद-हस्त है, आशीर्वाद है, उन

कम्पनीयों में क्या चल रहा है। भारत का जो शेअर कैपिटल है उस से डबल से भी अधिक उन्होंने एजेंटों से और वितरकों से डिपॉजिट इकट्ठा किया है मेरे पास यह 31 मार्च तक की बीनेसशीट है—इस में 2 करोड़ 18 लाख रुपया अकेले डिस्ट्रिब्यूटर्स से जमा किया गया है। मैं मंत्री जी से आज इस बात की सफाई चाहता हूँ—25 प्रतिशत का आप का रुल है या नहीं? शेअर कैपिटल का कितने प्रतिशत डिपॉजिट के रूप में पब्लिक से इकट्ठा किया जा सकता है—विभिन्न फोर्म में। क्या भारत के केवल एजेंटों से शेअर कैपिटल के दुगने में भी अधिक रुपया इकट्ठा किया है या नहीं।

आप दूसरी कम्पनियों से आप इस कम्पनी की बीनेसशीट की तुलना करेंगे तो आप को मालूम होगा कि बहुत सारी बातें जो कम्पनी कानून के तहत इस बीनेसशीट में होनी चाहिये, वे भी इस में नहीं आई हैं। विचित्र बात तो यह है कि 46 लाख रूपय की शेअर एप्लीकेशन इन के पास पड़ी हुई है, उस में से 20 लाख रुपया जमा है, लेकिन उन की एप्लीकेशन तक नहीं है। भारत में जितनी पूजा लगी हुई है, सब चोरो, बदमाशों और स्मगलरों ने लगाई हुई है वरना इस तरह की बात कम्पनी कानून के अन्तर्गत किस हो सकती है—मेरी समझ में नहीं आता है—पैसा जमा है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं है—इस का मतलब है कि सारे शेअर बोणस है, उन में ब्लैक का पैसा लगा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को 14 महीने हो गए—आप इस सदन के उपाध्यक्ष हैं, यह केवल अध्यक्ष की ही जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिलवाये, आप की भी जिम्मेदारी है, दूसरे संभाषितियों की भी जिम्मेदारी है जो इस कुर्सी पर बैठते हैं। 14 महीने हो गये मैंने पूछा था कि भारत के मेजर इन्वैस्टर्स बताने जायें और इकानामिक आफफिशियल के बारे में बतलाया जायें—मैंने दोनों सवाल क्रॉस में मिनिस्टर से पूछे थे—14 महीने

‡ [श्री मधु लिमये]

के बाद भी यह जानकारी नहीं मिली यह कहा जाता है कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है, उचित समय पर रखी जायगी। यह समय अब आयेंगा—मेरे मरने के बाद ?

प्रो० श्री नारायणचन्द्र पराजपूर (हमीर-पुर) : आप के हारने के बाद।

श्री मधु लिमये : हारने की उम्मीद न कीजिये—मेरे मरने के बाद ही यह इन्फॉर्मेशन आयेंगी। इसलिये मैं चाहता हूँ कि इन बातों का खुलासा हो जाय उसी तरह से हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड में अच्छा लेख आया है, मंत्री जी को पढ़ना चाहिये इसके बारे में।

"RBI regulations for deposits acceptance found inadequate".

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): If you remember aright, my amendment regarding over-subscription has been accepted and according to the modified and amended Companies Act, what Shri Limaye has said becomes very relevant and important, and this type of money being kept with the companies becomes an illegal act.

श्री मधु लिमये : आप के डायरेक्टर्स गारण्टी के बारे में यह कहते हैं कि कई डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं। उन के कोई असेट्स नहीं होते और शेयर कैपिटल का अगर 25 परसेंट पब्लिक से डायरेक्टर्स की गारण्टी पर लिया जायेगा तो बहुत सारी कम्पनियाँ ऐसी हैं जिस में पब्लिक हल्ला कर रही है कि हमारे डिपॉजिट्स वापस नहीं मिल रहे हैं। तो रिजर्व बैंक और सरकार किसी तरह का नियंत्रण कम्पनी ला का मामला हो या आर० बी० आई० का ही कोई नियंत्रण इन चीजों पर नहीं रख रहे हैं।

मैं मंत्री जी का ध्यान चिट फंड्स की ओर भी दिलाना चाहता हूँ यह भी एक माने

में नान-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स हैं और चिटफंड के कई मामले सरकार के सामने पड़े हुये हैं। उस में क्लास तीन और चार के जो बर्गकारी होते हैं वह अपनी बचत का पैसा लगाते हैं और उसमें करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है। तो क्या चिट फंड्स को भी नियमित करने के बारे में मंत्री महोदया कुछ सोचेंगे ?

इस विषयक का एक उद्देश्य यह है कि कृषि के कार्य में मदद दी जाय तो एक विषय की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मेरे पास 13 तारीख का 'हिन्दुस्तान टाइम्स' अखबार है और सिचाई के उपर एक लेख है।

"70 per cent of irrigation water goes waste".

हम लाग तो जानते थे लेकिन उन्हाने वही राज्या के आपसे प्रकृत करके दिया है और जानबूझकर इन का है वह आप के सामने रखता हूँ

"Wastage of water and lack of scientific water management were the other defects exposed. Only 30 per cent of water benefited crops, the rest being lost through seepage from canals or evaporation. This problem was worse in the major and medium irrigation schemes which accounted for 40 per cent of irrigation sources. Minor sources such as wells and tubewells provided irrigation of better quality."

इसलिये मैं कहना चाहता हूँ अभी आप ने पाँच डैम की खबर अखबारों में पढ़ी होगी कि पाँच डैम बन गया राजस्थान को फायदा होगा कि लेकिन लीकेज शुरू हो गया है और हर दिन 15,000 क्यूसेक्स से अधिक पानी चला जा रहा है और कहते हैं कि बाद में उस को किसी बैराज से पकड़ते हैं, तो मेजर और मीडियम इरीगेशन स्कीमों के ऊपर तो अरबों रुपया लगाया जा रहा है जिस से 30 प्रतिशत पानी बेकार जा है, नजदीक के इलाके है वहा इतना पानी होता है कि कभी कभी धान की फसले

मारी जाती है और जो दूर के इलाके कमान्ड एरिया में हैं उन को एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। एस्टीमेट्स कमेटी ने इस बात पर जोर दिया है कि ट्यूब वेल्स और पम्प सैट्स वर ही ज्यादा जोर दिया जाये ताकि किसानों के अस्तित्व में ही यह मामला रहे और इन के लिये रिजर्व बैंक में जो प्रयत्न कर रहे हैं उन दोनों में कोई समन्वय बैठना चाहिये। कृषि विभास के लिये बड़ी बड़ी योजनाओं पर पैसा बरबाद करने के बजाय जो आप की क्रेडिट है वह किसानों को दीजिये। और मैं ने मुझसे दिया था कि 14 नेशनलाइज्ड बैंक और स्टेट बैंक मिल कर एक कॉर्ड पम्पिंग सेंट कारपोरेशन बनाये और टर्न की बैलिस्म पर किसानों को दीजिये और उन पर इन्स्टालमेंट लगाया जाय। इस से बीच वाले जो पैसा अभी खोजा जाते हैं वह नहीं खोजे जायेंगे। मैं समझता हूँ उन भारों से मुक्ति को पर सरकार सोचेगी।

श्री मूल सचिव डा. (पानी) : मान्यवर, रिजर्व बैंक बिल पर जब अमेडमेंट पेश हो रहे थे तो मेरे विभाग में अर्थ कि रिजर्व बैंक का काम क्या है, उस की देश के लिये क्या उपाय करना है और क्या अर्चीवमेंट्स का चुनाव किस पर हम विचार कर रहे हैं। मैं ने कई बार देना जो अर्थिक सचिव कहते हैं उस में रिजर्व बैंक का रोल अदा कर रहा है। रिजर्व बैंक हमें गेडवाइस देना है और सब कुछ सांचा है, लेकिन अब हम के अर्चीवमेंट्स को देना तो मालूम हुआ कि रिजर्व बैंक के जो काम करने वाले हैं या तो उन की रिपोर्ट को हर साल हाउस में डिस्कस किया जाय, और उन के अर्चीवमेंट्स क्या हैं इस बारे में करन क्रेडिट रिजर्व कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हम जो अपने अर्चीवमेंट्स रखना चाहते थे वह पूरे नहीं हुए। और जो भी उन्होंने ने लोन दिया है उस से मालूम होता है, जो बार बार आप कहते हैं कि छोटे किसानों को लोन देना चाहते हैं, उस की रिपोर्ट में यह लिखा है:

"By and large, the leading levels in all the other States are relative-

ly low. Tamil Nadu is a significant instance in which the loan per head of population, which stood at Rs. 17.24 in 1963-64, came down to Rs. 12.93 in 1966-67. The lowest in the scale are Orissa (Rs. 4.95), Jammu and Kashmir (Rs. 4.09), Rajasthan (Rs. 3.78), West Bengal (Rs. 3.36), Bihar (Rs. 2.60) and Assam (Rs. 1.29). These figures, like those of total loans of advance given earlier, bring out firstly the relatively low levels of co-operative credit in most States, and secondly, the declining trend which has begun to appear in more than one State even after allowance is made for the increase in the population."

तो आज की जो क्रेडिट है मालूम होता है कि दो और तीन रु० पर कैपिटल भी उस को लोन नहीं मिला। और बार बार आप कहते हैं कि रिजर्व बैंक लोन देना चाहता है। कहते हैं कि कोऑपरेटिव सोसायटी में लोन मिल रहा है। उन का कहना है कि कुछ बड़े आदमियों को ही मारा कर्जा मिलता है। कोऑपरेटिव सोसायटीज में ब्रेन्डेड इन्टरस्ट्स को कर्जा मिलता है। रिजर्व बैंक क्या करता है? मैं ने कई बैंक की हालत का देखा है, बढ़ावा बैंक के गेनेरल, डायरेक्टर और मेजरमेंट का हाल देखा है उन ने अपने घर वालों को पैसा दे दिया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order, please. You may continue when this Bill is again taken up. We now proceed to Private Members' Business.

श्री गेंडा सिंह (पदरौना) : उपाध्यक्ष महोदय, जरा हमारी बात सुन लें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस शुरू हो गया।